



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24 ]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2000/फाल्गुन 16, 1921

No. 24 ]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2000/PHALGUNA 16, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2000

सं. टीएएमपी/9/2000-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 50क और धारा 50ख को सभी महापत्तनों द्वारा एक समान रूप से क्रियान्वित किए जाने के लिए संलग्न आदेश को अधिसूचित करता है।

मामला सं० टीएएमपी/9/2000-सामान्य

आदेश

(फरवरी, 2000 के चौथे दिन को पारित किया गया)

इस प्राधिकरण की यह उल्लिखित स्थिति रही है कि महापत्तनों में प्रशुल्क निर्धारण के मामले में एकसमान सिद्धांत, दृष्टिकोण और अवधारणाएं अपनाई जानी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चेन्नई में फरवरी, 98 में आयोजित कार्यशाला में अपनाए गए दिशानिर्देश हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं।

2. एक मुद्दा ऐसा है, जिस पर एकसमान पद्धति हो सकती है और वह मुद्दा महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 50क और धारा 50ख के क्रियान्वयन से संबंधित है।

2.1 धारा 50क में निम्नलिखित उल्लेख इस प्रकार है:—

“किसी पत्तन में ब्लास्ट में प्रवेश करने वाले और यात्रियों को वहन न करने वाले पोत पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर पर पत्तन देयता भारित की जाएगी और यह अन्यथा प्रभार्य दर के तीन-चौथाई से अधिक नहीं होगी।”

2.2 धारा 50ख में निम्नलिखित उल्लेख इस प्रकार है:—

“किसी पत्तन में जब कोई पोत प्रवेश करता है लेकिन वह कोई कार्गो अथवा यात्री न तो उतारता है और न ही लेता है (इस अपवाद के साथ कि मरम्मत के प्रयोजन के कारण आवश्यक होने पर माल उतराई और पुनः लदान), उस पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर पर पत्तन देयता भारित की जाएगी और यह अन्यथा प्रभार्य दर के आधे से अधिक नहीं होगी।”

3. यह देखा गया है कि इन प्रावधानों के संबंध में सभी महापत्तनों द्वारा एकसमान पद्धति का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशुल्क निर्धारण के मामले में एकसमानता अपनाने की प्राधिकरण की वचनबद्धता के एक भाग के रूप में इस मुद्दे को उक्त कानूनी प्रावधानों के एकसमान क्रियान्वयन के लिए अपनाया जा सकता है।

4. यहां उन दो मामलों का उल्लेख करना उचित होगा, जिनमें प्राधिकरण ने इस विषय में कार्रवाई की है:—

(i) मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईआईएल) बनाम मुंबई पत्तन न्यास एमबीपीटी का मामला [मामला सं० टीएएमपी/5/97—बीपीटी]—इस मामले में प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्णय किया है:—

“लंगरगाह में प्रचालनों से जुड़े आईआईएल पोतों पर पोत-संबद्ध प्रभारों का लगाया जाना औचित्यपूर्ण है, इस संशोधन के शर्ताधीन कि पत्तनदेयता महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 50ख में निर्धारित सामान्यतया प्रभार्य दर का केवल 50 प्रतिशत होगी।”

(ii) मैसर्स युनाइटेड लाइनर एजेंसीज ऑफ इंडिया प्रा० लिमिटेड (यूएलएआई) बनाम पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) का मामला [मामला सं० टीएएमपी/1/98—पीपीटी]—इस मामले में प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्णय किया है:—

“यात्राओं के बीच दिनों की संख्या और अन्यथा के परिप्रेक्ष्य की तुलना में इस परिप्रेक्ष्य में यूएलएआई के अनुरोध पर विचार करना अधिक तर्कसंगत होगा, जैसाकि भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी संघ द्वारा सही जोर दिया गया है कि ‘तटीय पोत’ और विशेषकर अन्य ‘विदेश जाने वाले पोत’ के संबंध में (परिणामी) कठिनाइयां हो सकती हैं। अन्य शब्दों में, खाली लैश नौकाओं को लेने के लिए ‘दूसरी यात्रा’ करने वाले लैश पोत को पत्तन में प्रवेश करने वाला माना जा सकता है, लेकिन महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 50ख में उल्लेख के अनुसार वह कोई कार्गो अथवा यात्री न तो उतारता है अथवा न ही लेता है। इस प्राधिकरण को ऐसे मामलों में सामान्य दर के आधे से अनधिक दर पर पत्तन देयता के लिए दर निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए, कानून के अधीन यह प्राधिकरण ऐसे मामलों के लिए 0 प्रतिशत दर भी निर्धारित कर सकता है। तदनुसार, दूसरी यात्रा करने पर पत्तन देयता की छूट देने संबंधी यूएलएआई की मांग को स्वीकार कर लिया गया था।”

5. सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करते हुए और समग्र ध्यान देने के पश्चात यह प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित निर्णय करता है:—

(i) महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 50क के संदर्भ में किसी पत्तन में ब्लास्ट में प्रवेश करने वाले और यात्रियों को वहन न करने वाले पोत पर पत्तन देयता अन्यथा प्रभार्य होने वाली दर का केवल 75 प्रतिशत भारित की जाएगी।

- (ii) महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 50ख के संदर्भ में किसी पत्तन में प्रवेश करने वाले लेकिन कोई कार्गो अथवा यात्री को न उतारने वाले अथवा न लेने वाले पोत पर पत्तन देयता अन्यथा प्रभार्य होने वाली दर का केवल 50 प्रतिशत भारित की जाएगी।
- (iii) खाली लैश नौकाओं को लेने के लिए 'दूसरी यात्रा' करने वाले लैश पोत को महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 50ख में उल्लेख के अनुसार पत्तन में प्रवेश करने वाला पोत माना जाएगा, लेकिन कोई कार्गो अथवा यात्री को उतारने वाला अथवा लेने वाला नहीं माना जा सकता और इस पर कोई पत्तन देयता भारित नहीं की जाएगी।

6.1 सभी महापत्तनों को एतद्वारा अपने दरों के मान में तदनुसार उपयुक्त परिवर्तन शामिल करने का निदेश दिया जाता है।

6.2 उपर्युक्त दो विशेष मामलों में पारित आदेशों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के यह आदेश भारत के राजपत्र में इसे अधिसूचित किए जाने के 30 दिन पश्चात् प्रचलान में आएगा।

एस० सत्यम, अध्यक्ष

[ विज्ञापन 3/4/असाधारण/143/99 ]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2000

**No. TAMP/9/2000-Genl.**—In exercise of the powers conferred by Section 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the Order appended hereto about implementation of Section 50A and Section 50B of the Major Port Trusts Act, 1963 uniformly by all the major ports.

### Case No. TAMP/9/2000-Genl.

## ORDER

( Passed on this 4th day of February 2000 )

It has been the stated position of this Authority to adopt uniform principles, approaches, and concepts in the matter of tariff fixation at the major ports. Towards this end, we have been guided by the Guidelines adopted at the Workshop held in Chennai in February 98.

2. One of the issues on which there can be uniform practice is in respect of implementation of Section 50A and Section 50B of the Major Port Trusts Act.

2.1. Section 50A *ibid* reads as follows:

*“A vessel entering any port in ballast and not carrying passengers shall be charged with the Port Due at a rate to be determined by the Authority and not exceeding three-fourths at the rate at which she would otherwise be chargeable”.*

2.2. Section 50B *ibid* reads as follows:

*“When a vessel enters a port but does not discharge or take in any cargo or passengers therein (with the exception of such unshipment and reshipment as may be necessary for purposes of repair), shall be charged with a Port Due at a rate to be determined by the Authority and not exceeding half the rate with which she would otherwise be chargeable.”*

3. It is observed that no uniform practice is being following by all the major ports in respect of these provisions. As a part of the Authority's commitment to adopt uniformity in the matter of tariff fixation, this issue can be adopted for uniform implementation of the said legal provisions.

4. It is relevant here to refer to two cases wherein this Authority has dealt with this matter:

- (i). The case of M/s. Ispat Industries Limited (IIL) Vs. the Mumbai Port Trust (MBPT) [Case No.TAMP/5/97-BPT] – In this case, the Authority has decided as follows:

“The levy of vessel-related charges on IIL vessels in connection with operations at the anchorage is justifiable subject to the modification that the port due shall be only 50% of the normally chargeable rate as stipulated in Section 50B of the Major Port Trusts Act.”

- (ii). The case of M/s. United Liner Agencies of India (P) Limited (ULAI) Vs. the Paradip Port Trust (PPT) [Case No.TAMP/1/98/PPT] – In this case, the Authority has decided as follows:

“It may be more logical to consider the ULAI request in this perspective rather than in the perspective of number of days between calls as otherwise, as rightly stressed by the Indian National Shipowners' Association, there may be (consequential) implications for 'coastal vessels' and certainly for other 'foreign-going vessels'. In other words, a LASH vessel making a 'second call' to pick up empty LASH barges can be treated as a vessel entering a port but not discharging or taking in any cargo or passengers therein as described in Section 50B of the Major Port Trusts Act. This Authority has the power in such cases to

prescribe a rate for the Port Due in such cases not exceeding half the normal rate. Under law, therefore, this Authority can even prescribe a 0% rate for such cases. Accordingly, the demand of the ULAI about waiver of Port Dues on second call was accepted."

5. Taking all the relevant facts into consideration, and after a collective application of mind, the Authority hereby decides as follows:

- (i). In terms of Section 50A of the Major Port Trusts Act, a vessel entering any port in ballast and not carrying passengers shall be charged with only 75% of the Port Dues with which she would otherwise be chargeable.
- (ii). In terms of Section 50B of the Major Port Trusts Act, a vessel entering a port but not discharging or taking in any cargo or passenger therein shall be charged with only 50% of the Port Dues with which she would otherwise be chargeable.
- (iii). A LASH vessel making a 'second call' to pick up empty LASH barges shall be treated as a vessel entering a port but not discharging or taking any cargo or passengers therein, as described in Section 50B of the Major Port Trusts Act, and shall not be charged any Port Dues.

6.1. All the major ports are hereby directed to introduce appropriate changes accordingly in their Scale of Rates.

6.2. Without prejudice to the orders passed in the two specific cases cited above, this order will come into operation 30 days after its Notification in the Gazette of India.

S. SATHYAM, Chairman

[Adv. III/IV/Ext./143/99]

68061/2000-2

